भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1589

दिनांक 09 दिसम्बर, 2025

कृषि अनुसंधान और नवोन्मेष के लिए निधि

1589. श्री देवुसिंह चौहान:
श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी:
डॉ. विनोद कुमार बिंद:
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:
श्री आलोक शर्मा:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्तमान वित्त वर्ष में देशभर में कृषि अनुसंधान, नवोन्मेष और प्रौद्योगिकी-संचालित कृषि के लिए बढ़ी हुई धनराशि निर्धारित की है, साथ ही विशेषकर ओडिशा जैसे जलवायु-संवेदनशील क्षेत्रों और कंधमाल जैसे जनजातीय जिलों के लिए प्राथमिकता वाले विषयों की पहचान की है;

(ख) क्या ओडिशा के दूरदराज के क्षेत्रों सहित किसानों को अनुसंधान परिणामों और तकनीकी समाधानों को हस्तांतरित करने में मौजूदा योजनाओं की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कोई व्यवस्थित समीक्षा की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो समितियों या विशेषज्ञ समूहों द्वारा रेखांकित किए गए प्रमुख निष्कर्ष और प्रमुख कमियां क्या हैं;

(घ) ओडिशा और विशेषकर कंधमाल सहित देश में नवोन्मेष के क्षेत्र-स्तरीय प्रसार और कार्यान्वयन में सुधार के लिए आईसीएआर संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) और केवीके के बीच समन्वय को सुदृढ़ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए है; और

(ड.) क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जीनोम एडिटिंग और सटीक कृषि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने में सहायता के लिए कृषि-स्टार्टअप और नवप्रवर्तकों के साथ सहयोग करने हेतु नए संस्थागत या डिजिटल ढांचे शुरू किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री
(श्री भागीरथ चौधरी)

(क) : जी, हाँ। सरकार ने वर्ष 2025-26 के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग (DARE)/ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) को रू 124.48 करोड़ बढ़ाकर दिए हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा प्रणाली (NARES) ने बाढ़, सूखा और लवण प्रभावित क्षेत्रों जैसी जलवायु संबंधी वाचालताओं (कठिनाईयों) के लिए विशिष्ट फसल किस्मों सहित जलवायु अनुकूल कृषि हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। विभाग ने ओडिशा के सभी जिलों के लिए जिला आकस्मिकता योजनाएं (DACPs) भी विकसित की हैं।

(ख) एवं (ग) : विभाग की सभी चलाई जा रही योजना स्कीमों का सावधिक एवं व्यवस्थित पुनरीक्षण तीसरे पक्ष की एजेंसियों द्वारा किया जाता है, जो भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निष्पादन परिणामों के लिए होता है। किसानों को तकनीकी समाधान उपलब्ध करवाने के लिए समीक्षा रिपोर्टों की संस्तुतियों के आधार पर स्कीम कार्यक्रमों/ गतिविधियों को संशोधित/ सुधार किया जाता है।

(घ) : किसानों के लिए वैज्ञानिक कृषि प्रौद्योगिकियों के प्रसार और विकास के लिए NARES हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) नोडल एजेंसी है। भाकृअनुप- अनुसंधान संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तथा कृषि विज्ञान केंद्र एक साथ मिलकर प्रौद्योगिकी विकास, परीक्षण और परिष्करण, प्रदर्शन और किसानों को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा विश्वविद्यालय स्तर पर भाकृअनुप, कृषि प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान (ATARI), कृषि विश्वविद्यालयों तथा प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समितियों द्वारा नियमित रूप से निगरानी और समीक्षा का कार्य किया जा रहा है। ओडिशा राज्य सहित देश में समन्वित अनुसंधान और विस्तार कार्यकलापों के लिए भाकृअनुप-राज्य समन्वय की 8 क्षेत्रीय समितियां कार्य कर रही हैं।

(ड.) : जी, हाँ। उभरती हुई प्रौद्योगिकियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, जीनोम एडिटिंग और परिशुद्ध कृषि के व्यापक अंगीकरण को सुगम्य बनाने के लिए DARE-ICAR द्वारा विभिन्न सरकारी और निजी संगठनों के साथ समन्वय किया गया है।

कृषि और संबंद्ध क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार हेतु परिशुद्ध कृषि पर नेटवर्क कार्यक्रम (NePPA), अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान कार्यक्रम (AICRP), राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल नवोन्मेषी कृषि (NICRA) तथा कृषि विज्ञान केंद्र परस्पर समन्वय से कार्य कर रहे हैं।

तकनीकी-उद्यमियों और एग्री स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने के लिए विभाग ने विभिन्न ICAR संस्थानों में एग्री बिजनेस इक्युबेशन सेन्टर्स (ABICs) स्थापित किए हैं।

सरकार की ''नमो ड्रोन दीदी'' स्कीम तकनीक चालित खेती को बढ़ावा देती है और साथ ही यह उन्नत दक्षता, वर्धित फसलोपज और प्रचालन की घटी हुई लागत और स्वयं सहायता समूह (SHGs) को सशक्तता प्रदान करती है।

******